- **भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता ने दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, छह विधायकों को भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई।**
- **केंद्र ने तीस वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में गैर–संचारी रोगों की जांच के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया।**
- **श्री विजयपुरम स्थित विकास एवं सुविधा कार्यालय की ओर से एम एस एम ई प्रतिस्पर्धी–लीन योजना पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।**
- **रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए डिफांइड रेडियो की खरीद के संबंध में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।**

<><><><><><><><>

भारतीय जनता पार्टी की पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के साथ छह कैबिनेट मंत्रियों–प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रवींद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह ने भी शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहे। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों ने भी समारोह शिरकत की। रेखा गुप्ता, दिल्ली की चौथी और भाजपा की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले पत्रकारों से बातचीत में रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने दिल्ली की जनता के कल्याण और विकास के लिए पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करने का संकल्प लिया। हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने शालीमार बाग विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। उन्होंने उन्नीस सौ बानब्बे में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वर्ष उन्नीस सौ छियानब्बे में वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनीं। वह दिल्ली में भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव भी रह चुकी हैं।

<><><><><><><><>

केंद्र ने आज एक विशेष गैर–संक्रामक रोग–एन सी डी स्क्रीनिंग अभियान की शुरुआत की। अभियान का उद्देश्य तीस वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी व्यक्तियों की पूरी तरह से स्क्रीनिंग करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य आम गैर–संक्रामक रोगों, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, और तीन सामान्य कैंसर – मुंह, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिए सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करना है। यह अभियान गैर–संक्रामक रोगों की समय रहते पहचान और उचित उपचार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है।

<><><><><><><><>

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के स्व–नियामक निकायों के लिए एक दिशा–निर्देश जारी किया है। इसे भारत के कानून और सूचना प्रौद्योगिकी नियम, दो हजार इक्कीस में निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आचार संहिता के अंतर्गत निर्धारित सामग्री के आयु आधारित वर्गीकरण के सख्त पालन पर जोर दिया। मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफार्मों से महिलाओं के अभद्र चित्रण अधिनियम, उन्नीस सौ छियासी, भारतीय न्याय संहिता दो हजार तेईस, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण–पोक्सो अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, दो हजार के प्रावधानों पर भी ध्यान देने को कहा है, जिनमें अश्लील या पोर्नोग्राफिक सामग्री का प्रकाशन दंडनीय अपराध है।

<><><><><><><><>

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण के लिए एक बार फिर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पहले चरण में छह लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि तेल, गैस और ऊर्जा, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, यात्रा और आतिथ्य, ऑटोमोटिव और कई अन्य क्षेत्रों सहित तीन सौ से अधिक कंपनियों ने युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए हैं। दूसरे चरण में, प्रत्येक आवेदक अधिकतम तीन इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकता है। यह योजना युवाओं को शीर्ष कंपनियों में बारह महीने की सशुल्क इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए तैयार की गई है।

<><><><><><><><>

श्री विजयपुरम स्थित विकास एवं सुविधा कार्यालय की एम एस एम ई शाखा ने उद्योग निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में एम एस एम ई प्रतिस्पर्धी–लीन योजना पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य उद्यमियों, स्टार्टअप्स और एम एस एम ई के बीच विभिन्न लीन उपकरणों और तकनीकों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। इसके अलावा इन्वेंट्री प्रबंधन में सुधार, स्थान का उचित उपयोग और ऊर्जा खपत को कम करके उत्पादकता, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। शाखा एम एस एम ई–डीएफओ के प्रभारी सहायक निदेशक जी.के. सिन्हा ने विभिन्न एम एस एम ई योजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

<><><><><><><>

पांडिचेरी विश्वविद्यालय के महासागर अध्ययन एवं समुद्री जीव विज्ञान विभाग के परिसर में रेड रिबन क्लब की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी और जी. बी. पंत अस्पताल के रक्त केंद्र के सहयोग से यह शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कुल छत्तीस यूनिट रक्तदान किया गया। प्रतिभागियों को रक्तदान के विभिन्न पहलुओं और महत्व के बारे में जानकारी दी गई।

<><><><><><><>

रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक सौ उनचास सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की खरीद के लिए नई दिल्ली में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक हजार दो सौ बीस करोड़ रुपये से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि ये अत्याधुनिक रेडियो उच्च गति के डेटा और सुरक्षित आवाज संचार के माध्यम से सुरक्षित और विश्वसनीय सूचना साझाकरण, सहयोग को सुनिश्चित करेगा। यह समुद्री प्रवर्तन कानून, खोज और बचाव अभियान, मत्स्य संरक्षण और समुद्री पर्यावरण संरक्षण सहित अपनी मुख्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तटरक्षक बल की क्षमताओं को भी मजबूत करेगा। इस अनुबंध का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ देश की विनिर्माण क्षमताओं तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने और विशेषज्ञता विकास को प्रोत्साहन देना है।

<><><><><><><>

आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस है। प्रतिवर्ष बीस फरवरी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला विश्व सामाजिक न्याय दिवस, समाज के भीतर और उनके बीच एकजुटता, सद्भाव और अवसर की समानता को बढ़ावा देते हुए गरीबी, बहिष्कार और बेरोजगारी को दूर करने की कार्रवाई के लिए एक वैश्विक आह्वान के रूप में कार्य करता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस की भावना के अनुरूप, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विधायी सुधारों, जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से सामाजिक–आर्थिक अंतर को पाटने के प्रयासों को तेज कर दिया है। यह दिन विकास और मानव सम्मान को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के व्यापक मिशन के साथ जुड़ा हुआ है। दो हजार नौ में शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा फ़्लोर जैसी पहल सभी के लिए बुनियादी सामाजिक गारंटी सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गाराचरमा में राजस्व विभाग ने दो सौ वर्ग मीटर अनाधिकृत जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया। इसके अलावा श्री विजयपुरम तहसील में सौ वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर जीआई पाइप का उपयोग करके एक अवैध संरचना को हटाया गया। दक्षिण अंडमान ज़िला उपायुक्त ने अतिक्रमण से जुड़ी किसी भी गतिविधि से आम जनता को दूर रहने को कहा है।

<><><><><><><>